the exotic weed seeds do not escape and get mixed up with our own produce, the distribution of imported wheat is being restricted to non-wheat growing areas.

Chief Ministers' meeting on Ration Quota

1851. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a meeting of Chief Ministers was held in September, 1987 for increase of ration quota for poor sections of society;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) Yes, Sir. A conference of Chief Ministers was held on 30 September, 1997 to review the implementation of Targeted Public Distribution System (TPDS). The issue of increase of ration quota for families Below Poverty Line (BPL) was discussed as one of the items in the agenda.

(b) In the conference, a consensus emerged broadly that while these allocation for the BPL families may be increased, there should be no reduction in the allocation for the Above Poverty Line (APL) families. By and large, the view was also to limit the consumer subsidy on foodgrains distributed under PDS.

(c) It has been decided to maintain status quo for the present in view of the constraints of Stocks of foodgrains as well as the high level of subsidy involved.

FCI out of Foodgrains Trade in Punjab

1852. SHRI RAJNATH SINGH 'SURYA':
SHRI RAM NATH KOVIND:
DR. RANBIR SINGH:

Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that State Government of Punjab has proposed to keep FCI out of foodgrains trade due to very slow paddy procurement by it in this season;

(b) if so, the details thereof and reasons therefor; and

(c) the reaction of the Central Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) No such proposal has been received from Punjab Government. Foodgrains are procured by the FCI and State procuring agencies jointly under price support scheme for Central Pool at Minimum Support Prices fixed by the Government.

(b) and (c) Do not arise.

दालों का आयात

1853. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दालों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया और उस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) दालों का आयात कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) दालों का आयात मुक्त रूप से अनुमत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा और कीमत नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1995-96	4.91	685.57
1996-97	6.55	890.34
1997-98	6.59	833.64

पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी खाते पर दालों का कोई आयात नहीं किया गया।

(ग) दालों के आयात में कमी लाने के प्रयोजन से दालों की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम नामतः राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

Oil imports affecting domestic solvent extraction plants

1854. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether excessive oil imports flooding the market have resulted in domestic solvent extraction plants plagued by excess idle capacity; and

(b) if so, the steps proposed to protect such domestic processors?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) Domestic solvent extraction plants are working to well below their installed capacity due to shortage or oil bearing material and not due to excessive oil imports. The Shortfall between demand and supply is currently estimated at between 14-15 lakh MTs. Against this, the import of 11.3 lakh MTs of edible oils in the financial year 1997-98 cannot be considered as excessive.

भारतीय खाद्य निगम को दी जाने वाली राज-सहायता

1855. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1994-95 से 1997-98 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि राज-सहायता के रूप में प्रदान की गई;

(ख) यह सहायता किस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई और तत्संबंधी राशि कितनी थी;

(ग) निगम द्वारा उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः कितनी धनराशि की मांग की गई थी; और

(घ) निगम को उक्त अवधि में वास्तव में कितना नुकसान हुआ था और हजनि के रूप में निगम को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) सरकार भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की इकनामिक लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं आदि के अधीन वितरण से उनकी बिक्री प्राप्ति के बीच के अन्तर के भुगतान उपभोक्ता सब्सिडि के रूप में करती है। बफर स्टाक रखने की लागत प्रतिपूर्ति भी निगम को खाद्य सब्सिडि के रूप में की जाती है। इसके अलावा, निगम को हुई मार्गस्थ और भण्डारण कमियों/हानियों की प्रतिपूर्ति भी इनको नियमित करने की निर्धारित कार्यावधि को अपनाकर इनको नियमित करने के बाद की जाती है। 1994-95 से 1997-98 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम की अनुमानित आवश्यकताओं के प्रति